□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

जनसत्ता 11 जुलाई, 2014 : कहा जाता है कि जब कोई साज न□ साजिंदे के हाथ में जाता है तो उससे अलहदा धुन निकलती है□ भारत निर्माण का नगा□ा पीट कर कांग्रेसी विदा हो चुके हैं और उनकी जगह 'भारत चमकने' का दावा करने वाली भाजपा ने नया बजट पेश किया है□ मगर बजट को देख कर लगता नहीं है कि यह जुदा नीतियों वाली नई सरकार का बजट है□ कांग्रेस की तरह भाजपा ने भी देश की आर्थिक सेहत सुधारने के नाम पर लोगों को जम कर क□वी दवा की खुराक पिलाई है□ अच्छे दिनों की आस में बल्लियों उछलने वालों का अब सच से सामना हुआ है□ उम्मीदों पर पानी फिर गया है□ मगर सवाल है कि इस बजट से किसके अच्छे दिन आ□ंगे□ जवाब के लि□ बजट पर नजर डालते हैं□

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में राजकोषीय घाटा रोकने पर सबसे ज्यादा जोर दिया है□ मौजूदा वित्तवर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.1 फीसद तक रखने का □लान किया गया है□ आने वाले सालों के लि□ 'राजकोषीय अनुशासन' के नाम पर वित्तवर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.6 फीसद और 2016-17 में जीडीपी के तीन फीसद के स्तर पर रखने की घोषणा की गई है□ नरेंद्र मोदी सरकार का बजट प□ कर किसी को गलतफहमी हो सकती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे ब□ी समस्या राजकोषीय घाटा है□ अगर इसे सरकार जीडीपी के तीन फीसद तक ले आई, तो अर्थव्यवस्था को ऊंची विकास दर के साथ आगे ब□ने से कोई रोक नहीं सकता है□

राजकोषीय घाटे के लि□ तय कि□ ग□ इन लक्ष्यों का मतलब है कि राजग सरकार आने वाले तीन सालों तक लगातार सादगीपूर्ण उपायों के जरि□ राजकोषीय घाटे में कटौती के नाम पर लोगों पर ज्यादा से ज्यादा बोझ डालेगी□ सादगीपूर्ण या कि□यतशारी का मतलब है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बजट में कटौती करेगी□ बताने की जरूरत नहीं कि सरकारी खर्च में कमी की सबसे ब□ी कीमत कम आमदनी वाले लोगों, खासकर हाशिये पर रहने वालों को चुकानी होगी□

चालू वित्तवर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.8 फीसद के आसपास रहने का अनुमान है□ क्या भारत में राजकोषीय घाटा खतरे का निशान पार कर गया है? जवाब है नहीं□ फिलवक्त भारत के आकार की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय घाटा जीडीपी के छह से आठ फीसद के आसपास है□ दरअसल, ऊंचा राजकोषीय घाटा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की पहचान है□ आज विकसित देशों की कतार में शामिल देश भी जब विकासशील दौर में थे, तो उनका राजकोषीय घाटा भारत के ही स्तर पर या उससे ज्यादा था□ जाहिर है, राजकोषीय घाटे का भूत ख□ा करके कोई और मकसद साधा जा रहा है□

दरअसल, राजकोषीय घाटा ऊंचा रहने के कारण कॉरपोरेट समूहों को निवेश पर मिलने वाले प्रतिफल में कमी आती है□ दुनिया के विकसित पूंजीपति देशों के गिरोह आइ□ एम□ एफ और विश्व बैंक से जब कोई देश कर्ज लेता है तो उसे इन संस्थानों का संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पैकेज) लागू करना होता है□ सरकारी खर्च में कमी करके राजकोषीय घाटे को कम से कम स्तर पर रखना इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा है□ अचरज नहीं होना चाहि□ कि वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण का ब□ा भाग राजकोषीय घाटे को काबू में करने के मुद्दे पर खर्च किया□

क□वी दवा के सिलसिले को आगे ब□ाते हु□ वित्तमंत्री ने बेहद नपे-तुले शब्दों में गरीबी निवारण के ले□ चलाई जा रही योजनाओं को तार्किक बनाने की घोषणा की है□ नव-उदारवाद में सबसिडी योजनाओं को तार्किक बना□ जाने का मतलब सरकार इनके बलि में कटौती करेगी□ पेट्रोलियम पदार्थों (पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और घरेलू गैस) पर सबसिडी घटाने का काम बजट से ठीक पहले जोर-शोर से शुरू किया जा चुका है□

उर्वरक सब्सिडी पर कैंची चलाने के लिए बजट में सरकार ने नई उर्वरक नीति की घोषणा की है। चूंकि बजट में वित्तमंत्री कह चुके हैं कि राजकोषीय घाटा कम करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए लोगों को सब्सिडी बिल में कटौती की मार सहने के लिए तैयार रहना चाहिए।

1990 से बड़ी पूंजी के सामने समर्पण की जो प्रक्रिया चल रही है, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले ही बजट में उसे चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। मसलन देश में हर दिन चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराने के वादे पर गौर करिए। हर पल बिजली का वादा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह बिजली बाजार दरों पर मिलेगी। सरकार इसकी कीमत में कोई रियायत नहीं देगी। जिसके पास बाजार भाव पर बिजली खरीदने का पैसा है, वह भुगतान करे और हरदम बिजली की सुविधा हासिल करे। गुजरात में यही हो रहा है। अचंभा होता है कि यह उस सरकार का बजट है, जिसने गद्दी संभालते ही संसद की पहली बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण की मार्फत दावा किया था कि इस सरकार पर पहला हक गरीबों का है।

यूपीए सरकार का सूपड़ा साफ होने की एक वजह बढ़ती महंगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही महंगाई कम करने का वादा किया था। यह बजट देख कर कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। बल्कि इसमें महंगाई की आग को और भड़काने का इंतजाम किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों समेत हर तरह की सब्सिडी में कमी, राजकोषीय घाटा काबू में करने के लिए सरकारी खर्च में कमी और महंगाई के संरचनात्मक कारणों की अनदेखी करना, कुछ ऐसी वजहें हैं, जो महंगाई की आग में घी का काम करेंगी।

महंगाई कम करने के नाम पर बजट में किए गए टोटकों पर गौर फरमाएं। सरकार का कहना है कि शहरों और कस्बों में किसान बाजार खोले जाएंगे। इन बाजारों की मार्फत किसान अपने कृषि उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेच पाएंगे। किसानों की ओर से की जाने वाली सीधी बिक्री महंगाई से लड़ने में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन असल मुद्दा संरचनात्मक ढांचे का है। हमारे देश में पैदा होने वाले फल-सब्जियों का चालीस फीसद हिस्सा शीत भंडारण सुविधाओं के अभाव में बर्बाद हो जाता है। किसानों के खेत से लेकर उपभोक्ता की मेज तक फल-सब्जी आपूर्ति की प्रणाली नहीं होने के कारण मांग और आपूर्ति के बीच का संतुलन गड़बड़ा जाता है।

बजट में शीत भंडारण सुविधाओं और आपूर्ति तंत्र विकसित करने की व्यापक योजना कहां है। बजट में पांच हजार करोड़ रुपए से गांवों में शीत भंडारण सुविधाओं का विकास करने की बात कही गई है। जरूरत के सामने नाकाफी इस रकम से शीत भंडारण सुविधाओं के विकास की बात पर अगर विश्वास कर भी लें तो अगला सवाल बिजली का है। बिजली के बिना गांवों में शीत भंडारण सुविधाओं का संचालन कैसे किया जाएगा। हमारे देश की मुद्रास्फीति, खासकर खाद्य वस्तुओं की ऊंची मुद्रास्फीति की एक वजह प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग और कम घरेलू आपूर्ति है। विडंबना देखिए, सरकार पांच सौ करोड़ रुपए से पूरे देश में दूसरी हरित क्रांति भी लाना चाहती है, साथ ही प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ा कर इनकी कीमतों में भी स्थिरता लाने का सपना देख रही है।

बजट में सबसे गहरी चोट मनरेगा पर की गई है। भाजपा शासित राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत सरकार के नुमाइंदों ने पहले ही इस बाबत संकेत दे दिए थे। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि मनरेगा में सुधार करके इस योजना को ठोस परिसंपत्ति निर्माण से जोड़ा जाएगा। ठोस परिसंपत्ति निर्माण का सीधा मतलब है कि अब सरकार इस योजना को निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों के हाथों की कठपुतली बनाने जा रही है।

याद रहे, पहले से ही मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम का पैंसठ से सत्तर फीसद कृषि और इससे जुड़ी सहायक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर वित्तवर्ष 2013-14 की पहली छमाही में अठहत्तर फीसद से ज्यादा काम जल संरक्षण, भूमि विकास और ग्रामीण पहुंच के क्षेत्रों में किया गया है। कहना न होगा, मनरेगा योजना के बुनियादी मूल्यों के साथ गंभीर छेड़छाड़ करने की राजग सरकार ने अपनी सामाजिक पक्षधरता खुले तौर पर जाहिर कर

दी है□

बजट में घोषति छोटी-छोटी योजनाओं की गहराई में जा□ तो यह तय करना मुश्कलि हो जा□गा कि बजट भाजपा केवत्तिमंत्री ने पेश कयिा है या कांग्रेस के वत्तिमंत्री ने□ बजट में सारे शहरों की महलिाओं की गरमिा सुनश्चिति करने केलि□ डे□ सौ करो□ रुप□ का प्रावधान कयिा गया है, वहीं सरदार पटेल की मूर्ति केलि□ दो सौ करो□ रुप□ का प्रावधान है□ महज सौ करो□ रुप□ में देश केब□ शहरों में मेट्रो रेल का जाल बछिाने का सब्जबाग दखिाया गया है, जबकि जानकारों का मानना है कि इस रकम से महज कसिी शहर में मेट्रो रेल का वकिास करने से पहले होने वाला सर्वेक्षण ही कयिा जा सक्ता है□ कांग्रेस की अगुआई वाली यूपी□ सरकार केपछिले दस बजटों में भी ऐसे छटिपुट प्रावधानों की भरमार थी□

दरअसल, यह □कसोची-समझी रणनीति का हस्सिा है□ □कतरफ बजट का व्यापक□ जेंडा देशी-वदिेशी पूंजी केपक्ष में रखा जाता है, वहीं दूसरी ओर पचास-सौ करो□ रुप□ केप्रावधान से जनता केउबलते आक्रोश पर राहत केछींटे मारे जाते हैं□ अगर इस तरह देश का वकिास होना होता तो भारत अब तक स्वर्ग बन गया होता□ यूपी□ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल केहर बजट में दो सौ से लेकर पांच सौ करो□ रुप□ तक का प्रावधान पूर्वी भारत में हरति क्रांति लाने केलि□ कयिा था□ हकीक्त सबकेसामने है□

बीते ढाई दशकों, खासकर पछिले दस साल से वदिेशी पूंजी की गहरी पक□ में फंस चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था को नई राह पर ले जाने का मौका नरेंद्र मोदी सरकार केपास था□ मगर मोदी सरकार ने नई राह पर चलने केबजाय उसी पटिी-पटिाई नव-उदारवादी डगर पर चलने का फैसला कयिा है, जसिकी कीमत आज पूरा यूरोप और अमेरकि चुका रहे हैं□ अर्थव्यवस्था को वदिेशी पूंजी केलि□ खोल कर नंगा करने की सनक केचलते □कसमय सभ्यता का ग□ रहा यूनान आज ब□ी पूंजी की दलाल साख नरि्धारण □जेंसयिों केरहनुमाई में सांस ले रहा है□ वत्तिीय घाटा कम करने की जदि ने जनता का जीवन नरक कर दयिा है और लोग स□कपर उतर आ□ हैं□ भारत केनीतिनरि्माताओं ने इससे सबक लेने केबजाय उसी बर्बादी की तरफ ब□ने का फैसला कयिा है□ अगर नई सरकार केबजट का कसिी को □कपंक्ति में नचिो□ चाहि□ तो क्हा जा सक्ता है कि बुरे दनि शुरू हो ग□ हैं□

फेसबुकपेज को लाइककरने केलि□ क्लकिकरें- https://www.facebook.com/Jansatta

ट्वटिर पेज पर फॉलो करने केलि□ क्लकिकरें- https://twitter.com/Jansatta